

प्रेषक,

आर० डी० पालीवाल,  
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,  
मा.उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,  
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक 24 जनवरी, 2008

विषय:- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 11 (1) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में 10 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के पदों की निरन्तरता बढ़ाया जाना ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-154/xiii-e-1/2008 Admin.A, दिनांक 11-01-08 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल 10 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के पदों का कार्यकाल शासनादेश संख्या-47/xxxvi(1)/2007, दिनांक 26 फरवरी, 2007 के क्रम में दिनांक 01-03-08 से दिनांक 28-02-09 तक अथवा नियमित नियुक्ति जो भी पहले हो, बशर्ते कि ये पद उसके पूर्व, बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जायें, बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजन-105-सिविल और सेशन न्यायालय-03-जिला तथा सेशन न्यायाधीश -00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामों डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-1252/वित्त अनुभाग-5/2008, दिनांक 22-01-08 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आर० डी० पालीवाल)  
सचिव ।

संख्या : ११/१/xxxvi(1)/2008 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
- 2- समस्त जिला न्यायाधीश/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
- 3- कार्मिक/नियुक्ति, अनुभाग/वित्त अनुभाग-5 ।
- 4- ✓ एन.आई.सी. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से  
(आलोक कुमार वर्मा)  
अपर सचिव ।